KLG-SK/2O/3.00

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत): उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल की एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी, जिसके लिए शिलाँग में एक बहुत बड़ा संस्थान खड़ा है, मगर विगत 15 सालों में उसकी बैठक नहीं हुई थी, उसमें नियुक्तियां नहीं हुई थीं। जब हमारी सरकार आई, तो उस संस्था को पुनर्जीवित किया गया, उसकी बैठक हुई और जिसके कारण विकास के रास्ते भी प्रशस्त हो गए। जो हम "सबका साथ" कहते हैं, तो यह केवल नारा नहीं होता, we live by the slogan. We define the slogan in such a way that it is translated into reality.

उपसभापति जी, दिव्यांगों की चर्चा भी इस सदन में हुई है। हमारे थावर चन्द गहलोत जी उस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब यह जानते हैं कि जितने सारे दिव्यांग हैं, उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए, उनको अंगदान करने के लिए कार्यक्रम होते हैं, जैसे जयपुर फुट दिए जाते हैं, अन्य दूसरे उपाय किए जाते हैं। अब ऐसे कार्यक्रम करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, मगर ये कार्यक्रम किए नहीं जाते थे, क्योंकि उनके बारे में कोई बहुत उत्साह नहीं होता था। केन्द्रीय मंत्रालय के द्वारा साल में मुश्किल से पच्चीस, तीस ऐसे कैम्प लगाए जाते थे, लेकिन जब से यह सरकार आई, तो सरकार ने यह सोचा कि हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्यों न हमारे जन-प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए? हमारे सभी सांसदों को, विधायकों को सरकार ने चिट्ठियां लिखीं कि ये कैम्प आप अपने-अपने चुनाव-क्षेत्र में ऑर्गेनाइज़ करिए, इससे आपको लाभ होगा और जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी लाभ होगा। इससे 300 परसेंट का इजाफा हुआ

और इस तरीके के 150 से भी अधिक कैम्प मात्र दो साल की अवधि में लगे। मैं मानता हूँ कि जब संवेदनशील होने वाले व्यक्ति सत्ता का नेतृत्व करते हैं, तब इस तरीके का परिणाम निकल कर आता है। इसलिए मैं इसका भी यहां आग्रह के साथ जिक्र करना चाहता हूँ।

उपसभापति जी, हम सब रेलवे के बारे में जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इस सरकार का बहुत अच्छा बल सोशल मीडिया पर रहा है। यह सोशल मीडिया कोई एक फैशन नहीं है, यह सोशल मीडिया कोई अपना स्टेटस बढ़ाने का औजार नहीं है, बल्कि इस सोशल मीडिया को जनता के उपयोग के लिए, उसकी पीड़ा, दुख-दर्द मिटाने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। कैसे? हम जानते हैं और हमने देखा है, आप सब लोग भी जानते हैं कि ट्विटर का उपयोग करते हुए हमारे रेल मंत्री का ध्यान आकर्षण करते हुए कई रेल यात्रियों ने अपनी पीड़ा का हरण किया। कोई महिला यात्रा कर रही थी, जिसने बच्चे के लिए दूध लिया था, जो खराब हो गया और गाड़ी रुकती नहीं थी, कोई फास्ट ट्रेन थी, तो उसने ट्वीट किया। इसके बाद उस गाड़ी को किसी दूसरे स्टेशन पर एक स्पेशल हॉल्ट दिया गया और उस बच्चे की आवश्यकता पूरी करने के लिए रेलवे के कर्मचारी दूध लेकर वहां उपस्थित हुए। That is called a Government with sensitivity. उदयपुर से हमारे एक मित्र ट्रेन से आ रहे थे। जब वे आ रहे थे, तो उनकी बहन भी साथ में सफर कर रही थी, जो दूसरे कंपार्टमेंट में थी। यात्रा में रात्रि का प्रवास होता है। जब वह रात्रि में थ्री ए.सी. कंपार्टमेंट में ऊपर की सीट पर थी, जब रात्रि का अंधेरा और घना हो गया, तो उसको लगा कि कुछ लोग उस कंपार्टमेंट में आए और उन्होंने शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी हुआ। यह अकेली महिला थी,

डर गई। उसने भाई को पूछा कि मैं क्या करूं? भाई ने कहा कि तुरंत ट्वीट करो, हो सकता है एक-आधे घंटे में कुछ कार्रवाई हो। उसने ट्वीट किया। संबंधित डिविज़नल रेलवे मैनेजर ने जो भी कॉग्नीजेंस लेना जरूरी था, वह लिया और आधे घंटे के अंदर जो भी उसको परेशान करने की स्थिति में थे, ऐसे शराबियों को हिरासत में लिया गया। यह होता है- Government that works.

उपसभापति जी, मैं यहां पर आपको यह बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि संवेदना यह सबसे अहम पहलू है, जो इस सरकार की चिंतनधारा है, जो सिद्धांत है, उसका। कई प्रधान मंत्री इस देश में हुए और उनमें कई प्रधानमंत्रियों ने दिवाली अपने-अपने तरीके से मनाई, मगर ये ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जो अपनी दिवाली मनाने के लिए हर बार सियाचिन जाते हैं, बॉर्डर एरिया में जाते हैं, जवानों के साथ अपने त्योहार का आनंद बांटते हैं। इसके लिए संवेदना जरूरी होती है, कृतज्ञता जरूरी होती है, केवल नारों से काम नहीं चलता। कल मैं वित्त मंत्री जी का बजट सुन रहा था। इस बजट के बारे में चर्चा तो बाद में होगी, मगर यह रेलवे यात्रा का ही विषय है, मुझे अच्छा लगा इतनी बारीकी से जाकर इसमें ऐसा किया गया। हमारे कई जवानों को कई बार आनन-फानन में यहां से आना-जाना पड़ता है, रेल यात्रा में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जब जाते हैं तो ऐन समय पर आरक्षण संभव नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में उनके लिए जो सुविधा आवश्यक होती है, माननीय वित्त मंत्री जी ने इतनी बारीकी में जाकर सोचते हुए उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए डिफेन्स पर्सोनेल की यात्रा को सुखद करने के लिए, हेसल-फ्री करने के लिए एक प्रावधान किया है। मैं इस समय वित्त मंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ,

क्योंकि इन्होंने इतनी बारीकी से इस बारे में सोचा है, which is something very rare.

(2पी/एकेजी-वाईएसआर पर जारी)

AKG-YSR/2P/3.05

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत) : उपसभापति जी, मैं आपको तीसरे पहलू पर ले जा रहा हूँ, जो इस सरकार की विशेषता के बारे में है और उसका नाम है - नवाचार, Innovation. Innovation की चर्चा तो हम काफी सुनते आए हैं और innovation को promote करने के लिए इस देश में इसके पहले भी प्रयत्न होते रहे, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ किया नहीं, मगर innovation, जिसको out of the box thinking कहते हैं, उसका क्रियान्वयन हमारी सरकार की governance की प्रक्रिया के अन्दर करना और लोगों को भी सचेत करना, लोगों का भी आह्वान करना कि आप सोचिए, अपनी प्रतिभा का परिचय दीजिए, आपके जो भी सुझाव हैं, उनका स्वागत है, इस पद्धति से खुले मन से इस विषय की ओर देखना, मैं मानता हूँ कि यह इस देश के governance के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह कोई जरूरी नहीं था कि पद्म पुरस्कारों के बारे में हमेशा एक secrecy का वातावरण रहे कि पता नहीं यह किसको मिलता है, क्या करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, किसको खुश रखना पड़ता है, nobody knows. अब क्या हुआ! अब सरकार ने आदेश कराया कि पद्म पुरस्कार के लिए आप इंटरनेट पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, आप जिस किसी को नामांकित करना चाहते हैं, आप उसका नाम दे दीजिए, उसके बारे में सरकार निर्णय करेगी। इतना खुलापन! पद्म पुरस्कारों के लिए कोई संविधान

संशोधन करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कोई ordinance निकालने की जरूरत नहीं थी। जब मन में इच्छा होती है, जब खुलेपन के प्रति एक प्रतिबद्धता होती है, तब यह हो सकता है। मैं मानता हूँ कि यह एक नवाचार का उदाहरण है कि इस तरह की बातों को हमने जनता के साथ बाँटा है, जनता के सुझाव माँगे हैं। अभी-अभी रवि शंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि कितने नामी-गिरामी लोगों को, जिनके बारे में एक दृष्टि से मैं कहता हूँ कि वे ऐसे talented व्यक्ति थे, जो अब तक इस देश और दुनिया के सामने नहीं आए थे, हम उनको प्रकाश में लाए हैं। । must sincerely thank the hon. Prime Minister.

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी देश के साथ संवाद करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी प्रधान मंत्री नेहरू जी के समय से हम देखते आए हैं कि 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, तो राष्ट्र के नाम प्रधान मंत्री जी का एक संदेश आता था और हम उसे बड़े चाव से सुनते थे। हम रेडियो लगाते थे, टीवी पर देखते थे। अब क्या हो रहा है! अब यह जरूरी नहीं कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी तक रुकें। हर महीने के अन्तिम रविवार को प्रधान मंत्री जी देश के साथ अपने मन की बात को साझा करते हैं। किसी ने आलोचना की कि यह प्रधान मंत्री के मन की बात है, तो मैं उनका ज्ञानवर्द्धन करना चाहूँगा कि यह उनके मन की बात जरूर है, मगर वे जनता से पूछते हैं कि बताइए, मैं क्या बताऊँ। इसलिए यह तो जन की बात है, जिसका केवल नाम 'मन की बात' है। इसे हम सबको समझना चाहिए। वे कई लोगों के उदाहरण देते हैं। लोगों के जो नामी-गिरामी प्रयास रहते हैं, जैसे अभी रवि शंकर प्रसाद जी के द्वारा उदाहरण दिया गया, ऐसी कई अनूठी कहानियाँ, उदाहरण, प्रसंग, इनका वर्णन करते हुए वे जनता को एक दृष्टि से संवाद की धारा में लाते हैं

और कहते हैं, अपने मन की बात को बाँटते हैं और उनके मन की बात को भी सुनते हैं। इसके कारण संवाद की प्रक्रिया चलती है, जो मैं मानता हूँ कि इस सरकार की कार्यशैली की जो एक नीति है, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

मान्यवर, हम जानते हैं कि विदेश में जाने वालों की संख्या बढ़ी है। पासपोर्ट ऑफिस में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इसको तो hassle free ...(व्यवधान)... नहीं, नवाचारों की बात है, तो आपको एकदम compartmental thinking करने की जरूरत नहीं है। Let us have a holistic approach. मैं यह कह रहा था कि हमने इसको पहले भी online के मामले में बहुत आसान किया था। गुप्ता जी, आप जानते हैं। इसलिए चीजों को आसान करना, सरल करना, मैं मानता हूँ कि पोस्ट ऑफिस को पासपोर्ट ऑफिस में तब्दील करना, इसके लिए कानूनन कोई ordinance लाने की या संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। लोगों की पीड़ा को जानने की, समझने की आवश्यकता थी। जब उसे समझने वाले व्यक्ति सत्ता में होते हैं, तो क्या होता है, इसके उदाहरण इन निर्णयों के द्वारा हमारे सामने आते हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आपको राज्यों में भी जो हो रहा है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब केन्द्र सरकार इतना बढ़िया काम करती है, तो प्रेरणा जिस तरीके से रिसाव होकर नीचे तक जाती है, उससे राज्यों में भी एक प्रेरणा बनती है। प्रधान मंत्री जी ने कहा था - Per drop, more crop. पानी की किल्लत, पानी की समस्या, खेती के लिए पानी की अनुपलब्धता, हम दुनिया भर की बातें वर्षों से सुनते आए हैं, मगर पहली बार यह हुआ है, आप कृपया सुन लीजिए, पहली बार यह हुआ है कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, कई राज्यों में water

table बढ़ाने के लिए बहुत कारगर प्रयास हुए हैं। इसके लिए महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार योजना शुरू हुई, यहाँ पर भामाशाह योजना शुरू हुई। यह कोई बेवजह नहीं है कि मध्य प्रदेश में खेती की जो विकास दर है, वह एकदम 18, 19, 20 परसेंट तक हो गई है।

(2 क्यू/एससीएच पर जारी)

-YSR/VKK-SCH/2Q/3.10

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE (CONTD.): There is some reason behind it. वहां यह जो सिंचाई की व्यवस्था हो गई, जो water-table बढ़ा, जो नदियों को जोड़ने का प्रयास हुआ, मैं मानता हूं कि यह सब कारगर ढंग से तभी होता है, जब केन्द्र में नेतृत्व करने वाली सरकार विकास की एक सोच लेकर, एक दिशा में, 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र लेकर आगे बढ़ने के इरादे से काम करती है।

मान्यवर, एक बार लोग पुनः कहेंगे कि आप बजट के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, मगर मुझे मोह हो रहा है और उसका कारण भी है। मैंने इससे पहले भी बजट के कई भाषण सुने। मैं सोच रहा था कि कहीं किसी ने इसका उल्लेख भी किया है या नहीं किया है, मगर जब हम क्रियान्वयन की बात करते हैं, तो क्रियान्वयन हवा में नहीं होता है, जमीन पर होता है। जब सामाजिक विकास की बात आती है, तो विकास का मतलब केवल infrastructure का विकास नहीं होता है। वह महत्वपूर्ण तो है, but, that is not just development. जब माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में IMR और MMR को कम करने की बात करते हैं, ऐसे में सामाजिक विकास

के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसको और अधिक प्रकाश में लाने की आवश्यकता नहीं है। It is very clear to everybody.

सर, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का एक महत्वपूर्ण पहलू और है, जिसके ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है बार-बार होने वाले चुनाव। उन्होंने simultaneous elections की बात की है। इसके बारे में इस सदन के अंदर और इसके बाहर कई बार चर्चा हुई है। माननीय आडवाणी जी ने भी एक बार कहा था कि यह देश ऐसी स्थिति में है कि we are in a perennial election mode. हर वक्त कहीं न कहीं पर कोई छोटा चुनाव या कोई बड़ा चुनाव हो रहा होता है। चुनाव की राजनीति का बोझ या pressure, जो सत्ता में बैठे हैं अथवा जो विपक्ष में बैठे हैं, सभी लोगों पर होता है। बार-बार चुनावों के कारण पैसे की बरबादी होती है, इस बात को तो हम सब जानते हैं। इसके कारण समय भी बरबाद होता है। अभी हम देख रहे हैं कि पहले इस सदन का कार्यकाल चलता था, लेकिन अब बीच में थोड़ा अवकाश है, क्योंकि बहुत सारे लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सदन की उपस्थिति पर भी उसका असर है। इसमें पैसे की बरबादी होती है, समय बहुत लगाना पड़ता है और लोक-लुभावन वायदों से भी हम खुद को बहुत ज्यादा मुक्त नहीं रख पाते, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में एक समानान्तर पद्धति से, समन्वित प्रयासों के माध्यम से, simultaneous election करवाने की बात माननीय प्रधान मंत्री जी ने बड़े आग्रह के साथ रखी है, जिसका विस्तृत उल्लेख माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है। मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सभी मान्यवरों से अवश्य अपील करूंगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण democratic reform है, जिसको इस

देश की जनता हम सबसे मांग रही है। मैं मानता हूं कि हमें जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए और simultaneous election को पूरा समर्थन देना चाहिए। अगर आने वाले दो-चार वर्षों में हम इसको क्रियान्वयन में ला पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे जैसे लोगों के द्वारा इस देश की जनता की बहुत बड़ी सेवा हो पाएगी।

माननीय उपसभापति जी, मैं अंतिम बिंदु पर आ रहा हूं और वह है क्रियान्वयन। देखिए, हमारे घोषणा पत्रों में, भाषणों में, नारों में, इरादों में बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, मगर जैसा कहते हैं कि शक्कर का स्वाद उसको खाने के बाद ही पता चलता है, वैसे ही आपके इरादे कितने अच्छे हैं, जब तक वे जमीनी धरातल पर नहीं उतरते, जब तक उनका क्रियान्वयन नहीं होता, तब तक उनके बारे में पता नहीं चलेगा। यह सरकार ऐसी सरकार है, जो क्रियान्वयन पर बल देती है, सबसे क्रियान्वयन का हिसाब-किताब मांगती है।

देखिए, प्रधान मंत्री बहुत आए, Administrative Reforms Commission की बहुत सारी reports आईं, संवैधानिक परिवर्तन भी हुए, मगर मैं एक प्रधान मंत्री ऐसा देख रहा हूं, जो योजनाओं के क्रियान्वयन में विश्वास रखता है। यह मैं flatter करने के लिए या प्रशंसा के पुल बांधने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हकीक़त के रूप में बता रहा हूं कि विगत दो सालों में जो प्रगति योजना शुरू हुई है, उसका वर्णन हम टीवी पर देखते रहते हैं। प्रधान मंत्री जी बैठते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ बैठते हैं, सामने स्क्रीन पर एक-एक राज्य का मुख्य सचिव आता है और उससे हिसाब-किताब मांगा जाता है कि भई, आपने यह कहा था कि आप इस काम को तीस दिनों में करेंगे, तो यह क्यों नहीं हुआ? अगर यहां का काम नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ और अगर वहां का काम नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? There is some

accountability now, तब जाकर good governance होता है। Good governance कोई नारा नहीं है, good governance has to be a part of our experience. We are trying through all our efforts to bring good governance at the experiential level. यह अनुभव की बात होनी चाहिए। यह केवल खोखला नारा नहीं है। इस सुशासन को मुहैया करने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसका रहस्य कहां है? मैं मानता हूं कि उसका रहस्य एक sense of purpose में है। सत्ता की राजनीति, सत्ता में आना, मंत्रिमंडल में आना, लाल बत्ती वाली गाड़ी, बंगले और लुटियंस का सारा वातावरण, यह सब बहुत ही आकर्षक है, मगर क्या हम केवल उसके लिए सत्ता में आए हैं? Are we not supposed to convert the democracy into a delivering democracy?

(Contd. by BHS/2R)

BHS-RPM/2R/3.15

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE (CONTD.): I think, this Government is convinced that that is our objective, that is our aim and, therefore, this Government, let me tell you, after so many decades, has brought a robust sense of purpose to the very process of democratic governance which is the most important contribution of this Government. उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वातावरण को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इसलिए सरकार के प्रति भी एक ओनरशिप बढ़नी चाहिए और ओनरशिप बढ़ाने का

प्रयास MyGov के माध्यम से हुआ है। जब ब्रिटिशर्स की सरकार थी, तब तो लोगों को अपनी सरकार है, ऐसा लगता नहीं था और बाद में भी जो सरकारें आईं उन्होंने भी अपनापन सृजन करने की बहुत सारी कोशिशें नहीं कीं और उसके कारण सरकार और जनता, रूल्ड एंड दि रूलर्स, इनके बीच में हमेशा एक अन्तर रहता आया है।

महोदय, मैं मानता हूं कि इस सरकार ने MyGov के माध्यम से सहभागिता को बढ़ाते हुए जितने सारे प्रयास किए हैं, उसके कारण इस अन्तर को मिटाने की एक बहुत सार्थक कोशिश हो रही है। इस वातावरण को यदि बढ़ावा देना है, तो कई सारी जो विभाजनकारी चीजें आती हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। मैं अभी बंगलादेश गया था। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी भी हमारे साथ थे। हम एक डेलीगेशन में गए थे। हम ढाका यूनिवर्सिटी में गए। यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमें बताया कि यहां का हर डिपार्टमेंट सरस्वती पूजी को एक उत्सव के रूप में मनाता है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल के एक क्षेत्र में सरस्वती पूजी को लेकर एक बवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए।

महोदय, हमने "सब का साथ, सब का विकास" का जो नारा दिया है, जो एक मंत्र दिया है, उसके आधार पर हमें सब को लेकर विकास की इस यात्रा में सबको सहभागी बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज यह देश की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर "तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें", इस भाव से भारत माता की सेवा में जुट जाएं। इस काम में जुटी हुई सरकार और इसके कामों के प्रति अपनी भावना को दर्शाने वाला माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन का जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं पूरी ताकत से समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Sahasrabuddhe. Thank you very much. Now, hon. Members, the Motion that has been moved and seconded is that an Address be presented to the President in the following terms:-

> "That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2017."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.546 to 555) by Shri Kiranmay Nanda; not present. Amendments (Nos.556 to 642) by Dr. T. Subbarami Reddy; not present. Amendments (Nos.643 to 644) by Shri Derek O' Brien.

SHRI DEREK O'BRIEN (WEST BENGAL): Sir, I move:

643. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:
"but regret that the Address fails to pay respect to the 135 lives lost due to demonetization and the hardship faced by farmers, textile, construction and plantation workers, small business owners, trading communities, fishermen, housewives, students and large sections of middle class."

644. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:
"but regret that the Address fails to mention that the Government imposed withdrawal and deposit limits, restricting the public to access their own hard earned money."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.645 to 651) by Shri Nazir Ahmed Laway.

SHRI NAZIR AHMED LAWAY (JAMMU & KASHMIR): Sir, I move:

645. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:
"but regret that the Address does not mention about the steps to develop tourism infrastructure in state of J&K which largely depends upon tourism sector."

646. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:
"but regret that the Address does not mention about any action plan for the resumption of peace talks with Pakistan."

647. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:
"but regret that the Address does not mention that an additional assistance of Rs 30000 crore will be provided in the budget for all round development of Jammu and Kashmir."

648. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:

"but regret that the Address does not mention that the recovery of loans from the farmers of Kashmir should be stopped and debt be waived off as the last year has witnessed a complete turmoil in the region and the loans taken could not be properly utilized."

649. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:
"but regret that the Address does not mention about the time frame to complete the Jammu-Srinagar National Highway Project."

650. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:
"but regret that the Address does not mention about the time frame of completion of Jammu-Srinagar Railway Project."

651. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:
"but regret that the Address does not mention about any action plan to deal with the problem of unemployment in the state of Jammu & Kashmir."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Motion and Amendments have already been moved. Both are open for discussion. Shri Ghulam Nabi Azad.

The questions were proposed.

(Followed by RL/2S)

PSV-RL/2S/3.20

नेता विरोधी दल (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं यहाँ माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए और माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो उन्होंने दोनों सदनों के एमपीज़ को परसों सेंट्रल हॉल में सम्बोधित किया।

माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, the year of 2016 has been a year of depression, recession, suppression and regression. मैं सोचता था कि ...(व्यवधान)...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Also frustration for some.

श्री गुलाम नबी आज़ादः सर, मैं सोचता हूँ कि उस तरफ से हमेशा अंग्रेज़ी में शायरी होती है, तो हिन्दी में थोड़ी हम भी पहल करें।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरी तबियत आज ठीक नहीं है और यह सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छी बात है, तो शायद जिस जोश से मैं बोलता हूँ, आज उस जोश से नहीं बोल पाऊँगा ...(व्यवधान)... Low Blood Pressure की वजह से।

सर, माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, उसमें कश्मीर के हालात के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है, प्रकट की गई है। यह चिन्ता स्वाभाविक है। सरकार को भी चिन्ता है, कश्मीर की जनता को भी चिन्ता है, विपक्ष को भी चिन्ता है, पूरे देशवासियों को भी चिन्ता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू में 'सबका साथ, सबका विकास' की बात कही और पूरी पार्टी तथा पूरी सरकार 24 घंटे सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हमेशा जम्मू-कश्मीर भारत का सिर या भारत का ताज़ माना जाता है और जम्मू-कश्मीर के बारे में, चाहे वह infiltration हो या बाकी हालात हों, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख है। माननीय प्रधान मंत्री जी जब प्रधान मंत्री बनने के बाद पहले कुछ महीनों में कश्मीर गए थे, तो आपने शुरुआत 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत' से की थी। सब लोग खुश हो गए थे, पूरा भारत खुश हो गया था, कश्मीर

की जनता खुश हो गई थी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जनता खुश हो गई थी कि कई अरसे के बाद 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत' की फिर बात की गई। लेकिन उस 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत' का क्या हुआ? ग़ालिब का एक शेर है, जो आज जम्मू-कश्मीर के लोग दोहराते हैंः

"तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना,

कि खुशी से मर न जाते, अगर ऐतबार होता।"

उस 'कश्मीरियत', उस 'जम्हूरियत' और उस 'इंसानियत' ने इन ढाई सालों में किस तरह से सिसक-सिसक कर दम तोड़ दिया, इसे पूरी दुनिया ने देख लिया है। 2016 में उस 'जम्हूरियत' और 'इंसानियत' का कत्ल हो गया।

(2टी/वीएनके पर जारी)

VNK-DC/2T/3.25

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत) : मैं आज कश्मीर की अवाम से शुरू नहीं करता हूँ, 1947 से लेकर आज तक हमारे फौजी केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्णाटक से लेकर ओडिशा, बंगाल से लेकर यूपी, बिहार, गुजरात से लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कोई भी कोना शायद नहीं होगा, जहां हमारे फौजी..... हमारे security forces उस कश्मीर का हिस्सा बन कर रह गए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। वह भी उस कश्मीरियत का एक हिस्सा बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आज उन फौजियों से शुरुआत करता हूँ कि कितने security forces के लोग मारे गए और कितने सीज़फायर वायलेशन्स हुए। मैं अगर यह कहूंगा कि 2014-15 और 2015-16

में सबसे ज्यादा सीज़फायर वायलेशन्स हुई हैं। जितनी सीज़फायर वायलेशन्स इन थोड़े से समय में एनडीए की सरकार में हुई हैं, शायद इतनी दस या बीस सालों में नहीं हुई हैं। अगर 2015-16 के ही आंकड़े लें, तो पाते हैं कि 2015 में आतंकवादियों के हमले से जितने security forces के लोग मारे गए, जानें ज़ाया हो गईं, उनकी संख्या 39 थी और पिछले साल इनकी संख्या बढ़ कर दोगुने से ज्यादा 82 हो गई और सैंकड़ों जख्मी हो गए, लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि बहुत इम्प्रूवमेंट है। यह चिंता का विषय है। चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए समाधान होना चाहिए। अगर सरकार इसको चिंता का विषय कहेगी, तो फिर मेरे ख्याल में पूरे देश को सरकार पर चिंता करनी चाहिए कि सरकार चिंता कर रही है। सरकार हल निकालती है, सरकार चिंता नहीं करती है, सरकार समाधान निकालती है, सरकार चिंता प्रकट नहीं करती है। चिंता तो जनता करती है। यह सरकार infiltration रोकने और हमारे security forces की जानें बचाने में असफल हुई। अगर मैं यह कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण में जो कश्मीर के बारे में, security forces के बारे में आपने कहा था, जब ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, इसकी वजह से 60 परसेंट आपकी पार्टी को मिला है, लेकिन आज कश्मीर के हालात ज्यादा खराब हो गए।

सर, मैं उन सिपाहियों और फौजियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनकी हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने में भारी बर्फबारी की वजह से avalanches में जानें चली गईं। Security forces की 20 जानें चली गईं, गुरेज में 14 फौजी मारे गए, 5 फौजी मछेल में मारे गए और मेजर अमित सोनमर्ग में बर्फ के नीचे आ गए, लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। उनको बर्फ से

निकाला गया था, लेकिन तीन दिन तक वे श्रीनगर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ता बंद था। इस संबंध में सरकार को मेरा एक सुझाव है कि 1998 से पहले बर्फ पड़ने से पहले security forces की कुछ जगहों से महफूज़ जगहों पर, सेफर जगहों पर लोकेशन की जाती थी, लेकिन 1998-99 के बाद उनको एक ही जगह रखा जाने लगा, चाहे वह सेफ जगह हो या नहीं हो और यह इत्तिफाक की बात है कि 1998 से लेकर आज तक दूसरी बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई। 1998 के बाद पहली बार 2008 में इतनी बर्फबारी हुई थी, लेकिन उस समय avalanches नहीं आए, बहुत कम आए, उसमें उतनी जानें नहीं गईं, लेकिन इस बार avalanches ज्यादा आए। मेरा यह सुझाव है कि उनके लिए दोबारा बंदोबस्त करना चाहिए, connectivity बढ़ानी चाहिए। हमारे पहाड़ों में वैसी connectivity नहीं है, जैसे कुछ बॉर्डर एरियाज़ में connectivity है। आप कच्छ में देखें, तो वहां जापान की जैसी सड़कें हैं।

(2यू/एनकेआर पर जारी)

NKR-KR/2U/3.30

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत) : जहां मैं 20 साल पहले की, 25 साल पहले की बात करता हूं, जब मैं वहां टूरिज्म मिनिस्टर था और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कच्छ जाता था, उस समय जापान जैसी सड़कें थीं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में और वहां के पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी बहुत कम है। उसका असर आम जनता पर तो पड़ता ही है, फौजियों पर भी पड़ता है और विशेष रूप से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जैसे ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, वे वहां से पैदल निकलना चाहें, तो उसमें भी कई दिन लग जाते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि विंटर के दौरान हमें वहां

खास ध्यान देना होगा क्योंकि इससे ज्यादा मैं यहां सजैशन नहीं दे सकता हूं, सरकार को अलग से विस्तार में बता सकता हूं।

इसके साथ ही, सिविलियन्स के साथ वहां क्या हुआ? बुरहान वानी के बाद जो हालात पैदा हुए, उसमें 90 से ज्यादा सिविलियन मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेज और जनता के बीच की लड़ाई के दौरान, मुठभेड़ के दौरान, और वह नम्बर बहुत बड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेज और जनता के बीच लॉ एंड आर्डर मेन्टेन करने में 90 से ज्यादा लोग मारे जाएं और 12,000 लोग जख्मी हो जाएं, एक छोटी सी स्टेट में, यह बहुत बड़ी संख्या है। उनमें से एक चौथाई लोग, जिन 12 हजार लोगों को पैलेट इंजरीज़ आईं, उनमें से खास तौर से बच्चों में पैलेट इंजरीज़ हो जाएं, बहुत सारे बच्चे हमेशा-हमेशा के लिए अपनी आंखें खो दें, इस बारे में जहां हमारे मीडिया में बहुत छपा, टेलीविजन में बहुत आया लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत छपा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक कहा, and I quote : "An Epidemic of 'Dead Eyes in Kashmir'"

ये घटनाएं सिर्फ हमारे देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहीं, दुनिया के हर कोने में इस पर चर्चा हुई। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है, प्रदेश के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन भारत के लिए ठीक नहीं है। जहां हम 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करते हैं, जहां देश का एक हिस्सा और वह भी सिर, यदि सिर ही महफूज़ न हो, सिर ही सुरक्षित न हो तो धड़ कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसलिए सिर को बचाने के लिए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को बचाने के लिए, इस देश का सिर बचाने के लिए, मेरे ख्याल में, इस सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

उसके बाद तकरीबन 10 हजार नौजवान लॉ एंड आर्डर को मेन्टेन करने के लिए

गिरफ्तार किए गए। उसमें से सैंकड़ों लोग पी.एस.ए. में डाल दिए गए। पी.एस.ए. में दो साल के लिए जेल में आप कम से कम रख सकते हैं, बिना किसी ट्रायल के। कर्फ्यू वहां 90 दिन रहा और इन 90 दिनों में से 53 दिन वहां, वैली में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से कहीं एक दिन के लिए भी कर्फ्यू में रिलैक्सेशन नहीं दी गई। यह 'सबका साथ, सबका विकास' नहीं कहलाता।

माननीय उपसभापति साहब, कश्मीर के बारे में, मैं आने वाले बजट सैशन में जब चर्चा होगी, उस समय अलग से बोलूंगा, लेकिन पिछले बीते साल, जहां भारत के ताज के हालात के बारे में मैंने चर्चा की, हमारे भारत का जो धड़ है, जिस्म है, उसमें पिछले एक साल में क्या हो गया। डिमॉनेटाइजेशन की वजह से, जब उस पर चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है, 24 घंटे होती है, भारतीय जनता पार्टी और मंत्री चर्चा करते हैं, मैं सोच रहा था कि इतनी घटनाएं होने के बाद, सरकार डिमॉनेटाइजेशन या नोटबंदी के बारे में कम से कम क्रेडिट लेने की कम कोशिश करेगी, चर्चा कम करेगी और अपोलोजेटिक ज्यादा होगी।

(DS/2W पर क्रमागत)

DS-KS/3.35/2W

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत) : ज्यादा apologetic होंगे, कोई remorse की बात होगी, पछतावे की बात होगी, माफी की बात होगी, लेकिन वह नहीं है। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में भी कैबिनेट ने डाला, उनके मुँह से भी तारीफ करवाई,

लेकिन इस demonetization में क्या है? इस नोटबंदी के बारे में सरकार की तरफ से जो शुरू में कहा गया था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, जो नकली नोट हैं, वे बन्द हो जाएँगे, terrorism खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, उन तीनों चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ा। जितना पैसा बाहर था, वह तकरीबन सब बैंकों में वापस आ गया, तो ब्लैक मनी रही कहाँ?

इसी के साथ-साथ terrorism की बात आती है। बाँदीपुरा, जो कि पीओके के साथ लगा हुआ कश्मीर का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जब हमारी पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा, तो उसकी जेब से दो-दो हजार के नोट निकले, जबकि तब नोटबंदी को कुछ हफ्ते ही हुए थे। शायद तब यहाँ के बहुत सारे एमपीज़ को भी चेक के द्वारा दो-दो हजार और चार-चार हजार रुपये नहीं मिले थे, लेकिन बांदीपुरा में उस आदमी की जेब में वे पहले ही पहुँच गए थे, तो यह तर्क भी गलत निकला।

अब मैं counterfeit currency के बारे में पढ़ना चाहूँगा, जो एक मजाक है। अभी तक कई जगह counterfeit पैसे पकड़े गए हैं। उसके साथ ही, मैं दो और चीज़ें बताता हूँ। भारत की हिस्ट्री में शायद यह पहली दफा हुआ होगा या मुझे नहीं मालूम यह विश्व की हिस्ट्री में भी पहली दफा हुआ हो। मेरे पास "The Times of India" पेपर है और दूसरा पेपर भी है। इसमें लिखा है 'Bapu goes missing from a bundle of genuine two thousand rupee notes.' इसमें बापू ही नहीं हैं। The Father of the Nation के बगैर भी सरकार ने नोट छाप दिए। यह भी पहली दफा है। "The Times of India" ने ये फोटोज़ छापे हैं और यह दूसरे पेपरों में भी हैं, जिसको मैं सदन में रखूँगा। दूसरा है, '500 rupee notes with one side printed and the other side blank found in Madhya Pradesh.' वह यह है। यह एक साइड से

प्रिंटेड है और दूसरी साइड से ब्लैंक है और फिर बैंक वाले कहते हैं कि यह भी ठीक है और वह भी ठीक है, यह प्रिंटिंग की गलती है। क्या यह टाइपिस्ट है? मैंने typographical error तो सुना था, लेकिन नोट पर गाँधी जी की फोटो न हो और नोट एक ही तरफ से छपे हों, यह हम पहली दफा सुन रहे हैं। हमसे ज्यादा शायद किसी और की इंटरनेशनल नॉलेज होगी, वह बता पाएगा कि किस देश में इस तरह के नोट्स छपते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है।

सर, इस demonetization में एक और चीज़ देखने में आई और हमारी आँखें खुलीं। उस समय हम एक हफ्ते में 2,000 रुपये ले सकते थे, फिर 4,000 रुपये ले सकते थे और फिर 4,500 रुपये ले सकते थे। यह कई हफ्तों के बाद 4,500 रुपये हुआ था। हमने यह तो सुना था कि अगर बैंक में लोन लेने जाओ, तो वे दो परसेंट officially नहीं, बल्कि unofficially लेते हैं, वरना आपका लोन पास नहीं होगा। यह हम बचपन से सुनते आए हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इनकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, लेकिन हमने यह पहली दफा देखा कि इस नोटबंदी के बाद बैंकों में दो दरवाजे हो गए। एक दरवाजे से 4,000-4,500 रुपये मजदूर को, किसान को, गरीब को, बूढ़े को, सड़क पर काम करने वाले को, एमपी को, लीडर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जा रहे थे। आप अगले दरवाजे से तो 4,000 रुपये ले सकते थे, लेकिन पिछले दरवाजे से लेने की कोई सीमा नहीं थी।

(2एक्स/एमसीएम पर जारी)

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत) : आप उसमें, कोई वह 10 करोड़ ले सकते हो, 20 करोड़ ले सकते हो, 50 करोड़ ले सकते हो। यह तो कह सकते हैं कि इस वक्त हिन्दुस्तान में बैंक के मैनेजर शायद सबसे ज्यादा अमीर हो गए। मैंने ये घर के आंकड़े नहीं बनाए हैं, ये पेपरों से मैंने लिए हैं। सर, नई दिल्ली में साढ़े तीन करोड़ लेते हुए एक आदमी पकड़ा गया, यह तभी, उन्हीं दिनों की बात है। यह सब नई करेंसी थी। यह नवम्बर-दिसम्बर की बात है। जनवरी के आंकड़े नहीं हैं, सेशन उन दिनों चला नहीं, मैंने तब उसके भी आंकड़े निकाले थे। 30 नवम्बर को दूसरा वाकया हुआ। 6 करोड़ रुपये आई0टी0 ऑफिशियल्स ने कर्णाटक, गोवा रीजन में पकड़े। 6 करोड़ में से 4 करोड़ 70 लाख रुपए नए नोट थे। अभी तब महीना पूरा नहीं हुआ था 30 नवम्बर को। 6 दिसम्बर को 35 लाख पकड़े गए। नाराज होंगे मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन बी0जे0पी0 के लीडर को वैस्ट बंगाल में एस0टी0एफ0 ने पकड़ा, जिसके पास 35 लाख के दो-दो हजार के नोट थे। उसके साथ ही सी0बी0आई0 ने और लोकल पुलिस ने गोवा में रेड किया, जहां डेढ़ करोड़ के नए नोट निकले। इसके साथ ही 8 दिसम्बर को चेन्नई में आई0टी0 ऑफिशियल्स ने एक racket bust किया, जहां 90 करोड़ रुपए सीज़ किए। इसमें 70 करोड़ रुपए नए थे। यह कौन सा बैंक है जिसमें अगले दरवाजे से 4 हजार निकलते हों और पिछले दरवाजे से 90 करोड़ निकले हैं। कहीं से तो गए हैं, या तो जहां प्रिंटिंग होती है वहां से गए हैं या बैंक से गए हैं, कहीं न कहीं से तो गए हैं। मैं सब जगह नहीं, लेकिन अगली जगह से 1 करोड़ 57 लाख, दूसरी जगह से 24 करोड़, फिर 7 करोड़ 2 लाख, फिर 5 करोड़ 7 लाख, फिर 8 करोड़ जिसमें से 2 करोड़ नए, 6 करोड़ पुराने। इसके बारे में भी तो डिसक्रेडिट सरकार को लेना पड़ेगा। यह डिसक्रेडिट कौन लेगा कि यह दो किस्म

की करेंसी कहां से चल रही थी, ब्लैक मनी। तो यह है ब्लैक मनी, जो जेनेरेट हुई है इस नोटबंदी की वजह से, जो पिछले दरवाजे से जाती। ब्लैक मनी यह है। ब्लैक मनी वह नहीं है जो बैंकों में जमा हुई है, जो लोगों ने जमा कर दी। यह ब्लैक मनी जेनेरेट हुई है। This is just a tip of the iceberg. कितने लोग पकड़े गए हैं। कितने हजारों करोड़ इस तरह से बदल लिए। इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा कि इंटरनेशनल प्रेस ने इसके बारे में क्या कहा। तो यह था ब्लैक मनी के बारे में, जो जेनेरेट हुई, खत्म तो नहीं हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब और बीच में होम मिनिस्टर साहब भी आए कि लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आज यह सब करो, आगे सब ठीक होगा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब मीडिया वाले पहुंच जाते थे बाइट लेने के लिए, तो लोग कहते थे कि परेशानी तो है लेकिन सब ठीक होगा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं और इसी शहर में रहते हैं, उसी हिन्दुस्तान में रहते हैं, इसी हिन्दुस्तान के वासी हैं, सरकार में रहने के बाद लोगों के साथ मिलना कम होता है, आना-जाना कम हो जाता है, सरकार की फाइल में गुम हो जाता है। विपक्ष ज्यादा घूमता है। पहले तीन दिन तो रिपोर्टिंग बढ़िया होती थी, क्योंकि पहले दो-तीन दिनों में लाइनों में जो लोग रहते थे, वे पैसे निकालने वाले होते थे। लेकिन जब सरकार की तरफ से और आर0एस0एस0, बी0जे0पी की तरफ से हिदायत हो गई कि सब आर0एस0एस0, बी0जे0पी0 वर्कर्स लाइनों में रहो और बाइट्स दे दो कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तब की यह बात है।

(2Y/SC पर जारी)

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत) : मैंने शुरू में कहा कि हम भी यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हैं तो ज़ाहिर है कि बाइट्स को dilute होना ही था। हमने दिल्ली के एक शहर में देखा कि बाज़ू वाली दुकान में, एटीएम में लोग हॉकी लेकर गए। जब एक 65 साल के आदमी ने आवाज़ उठायी तो उसको हॉकी से मारा। दुकान में जो हॉकी लेकर बैठा था, वह दुकानदार नहीं था, वह हॉकी वाला कहीं बाहर से आया था और उस आदमी को कितने stitches लगे, वह हमने देखा। वह सीपीएम का आदमी था, कांग्रेस का आदमी था, हमारा आदमी था - वह आपका आदमी था। इन पैंतरों से सरकार नहीं चलती। सर, Demonetization का, नोटबंदी का असर क्या हुआ? माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के बारे में उल्लेख किया गया है। In Kisan's welfare lies the nation's prosperity. बहुत अच्छा है - कहने को, देखने को, सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सरकार में किसानों का क्या हुआ? National Crime Records Bureau क्या कहता है? वह कहता है कि 2014-15 में किसानों की 42 परसेंट आत्महत्याएं, suicides बढ़ गए। इस प्रकार हम उनका वेलफेयर देख रहे हैं? इस नोटबंदी की वजह से किसानों के पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, fertilizer खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, insecticide के लिए पैसे नहीं थे, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे नहीं थे, ट्रैक्टर के लिए पैसे नहीं थे, तेल के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी हम वेलफेयर की बात करते हैं! हमारे वक्त में भी ऐसी स्थिति आयी थी जब किसानों से आत्महत्या करने का आह्वान किया या शुरुआत की। उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने सन् 2008 में उनके 72,000 करोड़ रुपए माफ किए। सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तरफ से प्रयास किया लेकिन हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के वाइस प्रेज़िडेंट राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में एक किसान यात्रा की, मैं उनके साथ कुछ

हफ्ते रहा और दो करोड़ मांग पत्र आ गए। हम माननीय प्रधान मंत्री जी के पास गए थे कि उनका कर्ज़ माफ करें। हम राष्ट्रपति जी के पास भी गए, उनसे भी कहा कि किसानों का कर्ज़ माफ होना चाहिए। सर, यूपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के घरों के सामने, सड़कों पर किसानों ने टमाटरों और आलुओं के ट्रकों के ट्रक फेंक दिए। कल मुझे यूपी का उरैया का एक किसान मिला। उसने कहा कि demonetization के पहले, जिसे देसी भाषा में पचास किलो का एक कट्टा कहते हैं, पचास किलो की एक बोरी आठ सौ रुपए में जाती थी। वह एक बोरी, जो आठ सौ रुपए में जाती थी, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए एक दिन के 125 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन demonetization के बाद उस बोरी की कीमत 800 रुपए से गिरकर 20 से 50 रुपए हो गयी। चूंकि बोरी की कीमत 20 से 50 रुपए हो गयी और उसका किराया 125 रुपए था, इसलिए हमने दस हज़ार बोरे फेंक दिए - दस हज़ार बोरे एक किसान ने फेंके। यह हाल सभी किसानों का है, यह घर-घर की कहानी है। किसान की ऐसी हालत कर दी है कि मुझे नहीं लगता है कि किसान अगले दस साल तक भी उठ पाएगा। सर, हमारी बहनें, बहू-बेटियां हमेशा पैसा बचाकर रखती हैं, बुरे समय के लिए कुछ पैसा बचाकर रखती हैं।

(2जैड-जीएस पर जारी)

GS-KLS/2Z/3.50

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत): उनके नोट भी कागज बन गए। हमने टेलिविजन पर देखा है कि सीनियर सिटीजन्स किस तरह से तीन, चार, पांच दिन लाइनों में लग कर चले जाते थे और कई सीनियर सिटीजन्स की जानें चली गईं। सर, कहीं सुना है कि 120 लोगों की किसी पॉलिसी की वजह से जानें चली गईं। यह

तो मीडिया में आया है, उनके नाम आए हैं। बूढ़े, नौजवान हार्ट अटैक की वजह से मर गए। छोटे मासूम बच्चे ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया, क्योंकि अस्पताल नहीं जा सके। सर, और तो और एक गर्भवती महिला जिसको अस्पताल में दाखिल होना था, उसके घर में और कोई नहीं था, शायद उसे अस्पताल में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। 9 महीने की गर्भवती भी लाइन में बैठ गई और लाइन में ही बच्चा पैदा हो गया। इससे ज्यादा और क्या आपकी सरकार कर सकती थी? आपने गर्भवती महिलाओं के भी बच्चे खड़े-खड़े लाइन में पैदा करवा दिए, 75 साल के बूढ़े को भी लाइन में खड़ा कर दिया, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया और फिर भी, नोटबंदी अद्भुत, यह अद्भुत नहीं है, यह भूत है। यह इस देश की जनता के लिए भूत बनकर आया है, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। भगवान के लिए, खुदा के लिए ऐसे भूत आप अपने पास ही रखिए। जनता में बिल्कुल मत छोड़िए।

लेबर्स का क्या हाल हुआ है? लेबर्स जेनरेशन तो कम हो गई, लेकिन जो लेबर थी, हमारा जो कंस्ट्रक्शन था, उसका क्या हाल हो गया? कंस्ट्रक्शन को लोग आमतौर पर सोचते हैं कि बड़ा ठेकेदार है बस, लेकिन कंस्ट्रक्शन के साथ कितनी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, यह आपको मालूम है। आप नोएडा जाइए। आजकल मैं यू0पी0 के इलेक्शन में जा रहा हूं और लोगों को बिठाकर पूछता हूं। वहां पर सब कंस्ट्रक्शन बंद है। एक कंस्ट्रक्शन से जब कुछ बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उससे कई हजार मजदूर रोजगार से वंचित हो जाते हैं, उनका रोजगार खत्म हो जाता है। रोजगार सिर्फ मजदूर का ही खत्म नहीं होता है बल्कि हजारों जो मेसन काम करते हैं, वे बेरोजगार हो जाते हैं। हजारों कारपेंटर्स होते हैं, वे बेरोजगार हो जाते हैं। लोहे की और स्टील

की जो फैक्टरियां हैं, वे बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बंद है और उस स्टील फैक्टरी में मालिक ही नहीं, बल्कि कितने entrepreneurs और कितने मजदूरों की नौकरी चली जाती है। बिल्डिंगों में सीमेंट लगता है, सीमेंट लेना बंद हो गया, तो सीमेंट की फैक्टरियों में हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। ईंट के भट्ठों में हजारों-लाखों मजदूर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद होने के कारण ईंटों का खरीदना बंद हो गया, इससे मजदूरों की मजदूरी चली गई। यह तो एक सेक्टर की मैं बात करता हूं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर, बाकी कितनी फैक्टरियां बंद हो गईं। गुजरात के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी खुद जानते हैं। कपड़े की इंडस्ट्री का क्या होगा? हैंडलूम्स का क्या होगा, डायमंड्स का क्या होगा? सूरत में बीजेपी को कोई पैसा नहीं देगा। हां, डरा-धमका कर आप ले लें, लेकिन प्यार से नहीं देंगे।

जीडीपी, मैं economist नहीं हूं, लेकिन दुनिया के economists कहते हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी, जो economist हैं, वे भी जीडीपी दो-ढाई परसेंट कम होने की बात करते हैं। सर, पूरे देश में हमारे पेपरों ने, टेलिविजन ने क्या कहा, उसकी सबको जानकारी है। चीफ जस्टिस की बैंच ने क्या कहा नोटबंदी पर, सबको मालूम है।

(HMS/3A पर जारी)

SSS-HMS/3.55/3A/

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत) : हाई कोट्र्स और कोलकता की हाई कोर्ट बेंच ने क्या कहा, इस की जानकारी सब को है, लेकिन दुनिया ने क्या कहा, मैं उसका एक

नमूना बताता हूं। What has the international media said about demonetization? I quote The New York Times. 'It called the plan "poorly thought out and executed", given the pain it would inflict and its small, temporary gains.' UK's The Guardian says, "Modi has brought havoc to India", saying that "the rich will not suffer, as corruptly acquired fortunes have almost all been converted to shares, gold and real estate", but the poor would be hit hard." The Economist of UK says and I quote, "cautionary tale of the reckless misuse of one of the most potent of policy tools: control over an economy's money". It said that demonetisation would make only limited strides in shrinking the black economy, but would affect all of India's 1.3 billion citizens, the poorest most of all." The Financial Times of UK says and I quote, "India's cash bonfire was poorly designed, and was too much, too soon". Steve Forbes in Forbes Magazine called the decision "breathtaking in its immorality". I quote again, "What India has done is, commit a massive theft of people's property without even the pretence of due process - a shocking move for a democratically elected government."

सर, यह मैंने रिसर्च नहीं की है। मैंने यह जानकारी गूगल से निकाली है, जिसे कोई भी निकाल सकता है। इसलिए यह कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है।

सर, हमने यहां हमेशा आवाज उठायी है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आवाज उठायी, जिस का हम पूरा समर्थन करते हैं। अगर सरकार और सर्जिकल

स्ट्राइक्स कराएगी तो हम उसे समर्थन देंगे, लेकिन लोकतंत्र में अपोजिशन को यह पूछने का हक होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने जवान मरे, कहां मरे? लेकिन हमने ज्यों ही नंबर पूछना शुरू किया तो हम एंटी-नेशनल हो गए, इस तरफ के वहां से लेकर यहां तक सब लोग एंटी-नेशनल हो गए। सर, हमने नोटबंदी के खिलाफ कहा, तो पूरी opposition ब्लैक मनी वाली हो गयी या हिंदी में जिसे कहते हैं, "चित भी तेरी, पट भी तेरी।" सरकार जो भी पॉलिसी लाए, अगर उसे क्वेश्चन करो, तो या तो आप एंटी-नेशनल हो गए या ब्लैक मनी वाले हो गए। यह एक तरीका अच्छा निकाला। इसलिए चुप रहो, हम जो करते हैं उसे सुनो वरना एंटी-नेशनल कहलाओगे। सर, मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि जहां भी प्लानिंग में shortcomings रही हैं या lack of planning रही है, उसका कारण था कि एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं किया गया, पैसे का बफर स्टॉक नहीं था, एटीएम्स फंक्शन नहीं कर रहे थे। सर, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सरकार का यह भी रिकॉर्ड जाएगा कि किसी एक पॉलिसी को implement करने के लिए 50 दिनों में 135 दफा सर्कुलर इश्यू करने की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ी। यह है "भूत", इस अद्भुत को हम मानने के लिए तैयार हैं कि यह गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड बन गया कि किसी एक पॉलिसी को, चूंकि वह इतनी ill-conceived policy थी कि उस ill-conceived policy को बगैर सोचे-समझे implement करने के लिए 120 से 135 दफा सर्कुलर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजने पड़े हैं।

(3बी/एएससी पर जारी)